भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **1970**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 6 दिसंबर, 2024/15 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक में आत्मनिर्भर भारत

1970. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:
श्री ज्ञानेश्वर पाटील:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही है अथवा ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने उर्वरक उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाकर कुल उर्वरक खपत में घरेलू उर्वरक उद्योग की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है;
(ग) यदि हां, तो महाराष्ट्र, दादरा और नागर हवेली तथा मध्य प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार/जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या विगत पांच वर्षों में सरकार के प्रयासों से उर्वरक क्षेत्र के योगदान से देश के सकल घरेलू उत्पाद को बेहतर बनाने में मदद मिली है; और
(ड.) यदि हां, तो महाराष्ट्र, दादरा और नागर हवेली तथा मध्य प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): यूरिया के संबंध में, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामत: गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमश: उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-।।। यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख

मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा कार्यकुशल हैं क्योंकि ये अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अत:, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान की 207.54 एलएमटीपीए की कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता (पुनर्आकलित क्षमता, आरएसी) बढ़कर वर्तमान में 283.74 एलएमटीपीए हो गई है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने आरएसी के अतिरिक्त स्वदेशी यूरिया उत्पादन को बढ़ाकर अधिकतम करने के एक उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 भी अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 से यूरिया का उत्पादन 2014-15 के दौरान हुए वार्षिक उत्पादन की तुलना में 20-25 एलएमटीपीए तक अतिरिक्त बढ़ा है।

इन उपायों से यूरिया उत्पादन 2014-15 के दौरान 225 एलएमटी प्रतिवर्ष से बढ़कर 2023-24 के दौरान रिकार्ड यूरिया उत्पादन 314.07 एलएमटी हो गया है।

पीएण्डके उर्वरकों के संबंध में, सरकार ने फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए 1.4.2010 से पोषक-तत्व आधारित सबसिडी नीति लागू की है। नीति के अंतर्गत पीएण्डके उर्वरकों पर उनकी पोषक-तत्व मात्रा के आधार पर उर्वरकों के आयात मूल्यों और देश में पोषक तत्वों की आवश्यकता, उर्वरकों का संतुलित उपयोग, सब्सिडी और एमआरपी आदि जैसे अन्य संगत कारकों पर आधारित वार्षिक/अर्ध-वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक नियत राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा, पीएण्डके उर्वरक मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत आते हैं और कंपनियां अपने कारोबार के उतार-चढ़ाव के अनुसार इन उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए, उत्पादन को बढ़ावा देने और उर्वरक उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से एनबीएस सब्सिडी स्कीम के तहत नई उत्पादन इकाइयों या मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि को मान्यता दी गई है/रिकॉर्ड में लिया गया है। इसके अतिरिक्त, शीरे (पीडीएम) से प्राप्त पोटाश, जो 100% स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है, को बढ़ावा देने के लिए इसे 13.10.2021 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) प्रणाली के तहत अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा, एसएसपी पर मालभाड़ा सब्सिडी, जो एक स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है, को खरीफ 2022 से लागू किया गया है ताकि मृदा को फॉस्फेटयुक्त या "पी" पोषक तत्व प्रदान करने के लिए एसएसपी के उपयोग को बढ़ावा देने में मदद मिल सके। इन उपायों से वर्ष 2014-15 में 159.54 एलएमटी से पीएण्डके उर्वरकों का उत्पादन बढ़कर वर्ष 2023-24 में 182.85 तक हो गया है।

(घ) और (ड.): जी, हां। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में उल्लेख किया गया है कि भारतीय कृषि क्षेत्र लगभग 42.3 प्रतिशत आबादी को आजीविका सहायता प्रदान करता है और मौजूदा कीमतों पर देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी 18.2 प्रतिशत है। देश में अधिकतम कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए उर्वरक, पानी और बीज महत्वपूर्ण आदान हैं। सरकार ने पिछले दशक के दौरान विभिन्न प्रयास किए हैं जिसके कारण कुल सभी उर्वरक उत्पादन 2014-15 में 385.39 एलएमटी से बढ़कर 2023-24 में 503.35 एलएमटी हो गया है।

देश में कुल उर्वरक उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए गए जैसे कि यूरिया सब्सिडी स्कीम, नई यूरिया नीति 2015, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी स्कीम आदि।

****